पंजाब राज्य

बनाम

भाग सिंह

16 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति दोराईस्वामी राजू और न्यायाधिपति अरिजीत पासायत]

अभ्यास और प्रक्रियाः

निर्णय- कारण- देना- विचारण अदालत द्वारा बरी किए गए अभियुक्त- उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) के तहत अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया बिना कारण बताए-की शुद्धता- आयोजित किया : कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं- तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है- उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया-राज्य को अपील करने की अनुमति दी गई।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 141-विधि की घोषणा-न्यायिक अनुशासन का पालन करना आयोजित किया गयाः किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी त्याग नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादी-अभियुक्त पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 18 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। विचारण न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष का संस्करण पूरी तरह से आधिकारिक गवाहों

की गवाही पर निर्भर था और चूंकि कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं था, अभियोजन पक्ष का संस्करण असुरक्षित था और इसलिए, आरोपी को बरी कर दिया गया। अपीलकर्ता-राज्य ने अपील की अनुमति देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(3) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए अर्जी खारिज कर दी। इसलिए याचिका दायर की गई है।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह कारणों का संकेत दे कि अनुदान के लिए प्रार्थना क्यों की गई अपील करने की अनुमति को असमर्थनीय पाया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. विचारण अदालत को पूरे साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता थी। यदि न्यायालय इस संबंध में एक चूकपर था , तो उच्च न्यायालय अपील पर विचार करके इस तरह की कवायद करने के लिए बाध्य था। इस तथ्यों पर विचारण न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया , जैसा कि कानून द्वारा उसे आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों में अनुमति देनी चाहिए थी और उसके बाद प्रथम अपील पर न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना की और अभियुक्त के अपराध या अन्यथा अपराध के संबंध में अपने निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से वापस करना चाहिए था। यह ऐसा करने में विफल रहा है।

इसमें शामिल प्रश्न मामूली नहीं थे । स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता और आधिकारिक गवाहों की गवाही को अस्वीकार करना, भले ही वह विश्वसनीय, ठोस या विश्वसनीय हो।

अपील में विश्वसनीय निर्णय की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय ने बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है। और इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान प्रतीत होता है कि इस तरह के इनकार से, अपीलीय मंच द्वारा बरी किए जाने के आदेश की गहन जांच हमेशा के लिए खो गई है। कारण एक क्रम में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय के स्पष्टतम विचार पर, उच्च न्यायालय ने अपने कारणों को, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, अपने क्रम में अपने दिमाग के उपयोग का संकेत देना चाहिए था, और भी अधिक जब इसका आदेश आगे की चुनौती के लिए उपयुक्त हो। कारणों की अनुपस्थिति ने प्रस्तुत किया है उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है। [907 - जी-एच; 908-ए-डी]

यू. पी. राज्य बनाम बट्टन, [2001] 10 एस. सी. सी. 607; महाराष्ट्र राज्य बनाम विठ्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण ए आई आर(1982) एस सी 1215 और जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह, [1987] 2 एस. सी. सी. 222 पर भरोसा किया।

1.2 इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा का पालन करने के लिए न्यायिक अनुशासन को किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी भी बहाने से नहीं छोड़ा

जा सकता है, चाहे वह किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय हो, संविधान के अनुच्छेद 141 से बेखबर। [988 - ई-एफ]

2. कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। जिस पर जोर दिया गया है कारण दर्ज करना यह है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे" को प्रकट करता है यह अपनी खामोशी से न्यायालयों को अपना अपीलीय कार्य करने या न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के लिएनिर्णय की वैधता का निर्णय लेने में समीक्षा की शक्ति को लगभग असंभव बना सकता है । तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का अपरिहार्य हिस्सा है, कम से कम न्यायालय के समक्ष मामले में दिमाग के अनुप्रयोग को इंगित करने के लिए पर्याप्त कारण है। एक अन्य इसका कारण यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों किया गया है।प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स की गूढ़ शक्ति" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत होता है।[908 - एच; 909-ए-सी]

ब्रीन बनाम समामेलित अभियांत्रिकी संघ, [1971] 1 ऑल ई. आर. 1148 और अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री (1974) एल. सी. आर. 120, संदर्भित।

3. उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय अस्थिर है और अलग रखा जाता है। अपीलार्थी-राज्य को अपील दायर करने की अनुमति दी जाती है। [909 - सी-डी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 778 /1997

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सी. आर. एल. एम. संख्या 163-एम. ए. 1997 में दिनांक 24.4.97 के निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी की ओर से बिमल रॉय जड़ और सुश्री सुमिता पंडित

प्रतिवादी की ओर से आर सी कौशिक (एन पी)

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति अरिजित पसायत

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 378(3} के संदर्भ में बरी करने के प्रश्न की अनुमति देने से इंकार करना चुनौती का विषय है। अपीलकर्ता-पंजाब राज्य के अनुसार एक पंक्ति " बिना कारण बताए उच्च न्यायालय का खारिज किया गया आदेश कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। प्रतिवादी (यहां बाद में 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित) को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में अधिनियम') की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। अभियोजन पक्ष का संस्करण यह था कि 26.4.1995 पर आरोपी के पास एक किलोग्राम वजन की बड़ी मात्रा में अफीम अवैध रूप से पाई गई थी जिसे एक थैले में ले जाया जा रहा था। आरोपी को पकड़ने वाले अधिकारी ने उसे सूचित किया कि अगर वह चाहता है कि बैग की तलाशी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ली जाए, तो वह अपनी पसंद का संकेत दे सकता है

तथापि अभियुक्त ने पुलिस उप-निरीक्षक पर विश्वास व्यक्त किया जिसने अभियुक्त को पकड़ लिया था। नमूने एकत्र कर रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए। चूंकि नमूनों में अफीम पाई गई थी, इसलिए जांच पूरी होने पर आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए चालान किया गया था। संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान आरोपी ने इनकार किया आरोप लगाया और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया।

विचारण अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष का बयान पूरी तरह से आधिकारिक गवाहों की गवाही पर निर्भर था और चूंकि कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष का संस्करण कमजोर था। यह नोट किया गया कि तलाशी और जब्ती बहुत कम समय में की गई थी और यह अविश्वसनीय है कि कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं था। इसलिए विचारण अदालत ने बरी करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी-राज्य ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जिसने छुट्टी देने से इनकार कर दिया और छुट्टी के लिए आवेदन का निम्नलिखित तरीके से निपटारा कियाः

" सुना है, कोई योग्यता नहीं। खारिज कर दिया गया।"

अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार उच्च न्यायालय पर यह कारण बताना अनिवार्य था कि छुट्टी देने की प्रार्थना क्यों असमर्थनीय पाई गई। ऐसे किसी भी कारण के अभाव में उच्च न्यायालय का आदेश अक्षम्य है। संहिता की धारा 378 (3) बरी होने

की स्थिति में अनुमति देने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। संहिता की धारा 378 (1) और (3) इस प्रकार हैः

"378 (1) उप-धारा (2) में अन्यथा दिए गए प्रावधान को छोड़कर उप-धारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को मूल या अपीलीय याचिका से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है -उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति करने का आदेश या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति करने का आदेश।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी भी अपील पर उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना विचार नहीं किया जाएगा।

विचारण अदालत को पूरे साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी और फिर एक निष्कर्ष पर आते हैं। यदि विचारण न्यायालय इस संबंध में चूक कर रहा था उच्च न्यायालय अपील पर विचार करके ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य था। इस मामले के तथ्यों पर विचारण न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जैसा कि कानून द्वारा उसे आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों में अनुमति देनी चाहिए थी और उसके बाद अपील की पहली अदालत के रूप में, स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की समीक्षा करनी चाहिए और अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के संबंध में अपने निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से वापस करना चाहिए। वह ऐसा करने में विफल रहे। इसमें शामिल प्रश्न तुच्छ नहीं थे। स्वतंत्र गवाह

की आवश्यकता और आधिकारिक गवाहों की गवाही को खारिज करना, भले ही वह विश्वसनीय, ठोस या भरोसेमंद हो, अपील में निर्णय की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है, और इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान प्रतीत होता है कि इस तरह के इनकार से, अपील मंच द्वारा बरी किए जाने के आदेश की बारीकी से जांचकी गई है। एक बार और हमेशा के लिए खो गई है। जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार किया गया है, वह वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। कारण एक क्रम में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय पर स्पष्ट रूप से विचार करने पर, उच्च न्यायालय को अपने कारणों को, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, अपने आदेश में अपने दिमाग के उपयोग का संकेत देना चाहिए था, और भी अधिक जब उसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो।

कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के आदेश को टिकाऊ नहीं बना दिया है। यू. पी. राज्य बनाम बट्टन और अन्य, [2001] 10 एससीसी 607 में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। । लगभग दो दशक पहले महाराष्ट्र राज्य बनाम विठ्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण, ए. आई. आर. (1982) एस. सी. 1215 ने छुट्टी देने के आवेदन पर विचार करते समय बोलने के आदेश की वांछनीयता पर प्रकाश डाला। ऐसे मामलों में कारणों को इंगित करने की आवश्यकता न्यायिक रूप से की गई है।अनिवार्य के रूप में मान्यता प्राप्त। इस दृष्टिकोण को जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह और अन्य, [1987] 2 एससीसी 222 में दोहराया गया था। इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा

का पालन करने के लिए न्यायिक अनुशासन को किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी भी बहाने से नहीं छोड़ा जा सकता है, चाहे वह किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय ही क्यो ना हो। भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 141 (संक्षेप में 'संविधान')।

यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में लॉर्ड डेनिंग ने एम. आर. ब्रीन बनाम समामेलित अभियांत्रिकी संघ, [1971] 1 सभी ई. आर. 1148 का अवलोकन किया गया

> "कारण बताना अच्छे प्रशासन के मूल सिद्धांतों में से एक है। अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री, (1974) एल. सी. आर. 120 में यह देखा गया थाः कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है। कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग और विचाराधीन विवाद और निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने के बीच जीवंत संबंध हैं। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं।"

कारणों को दर्ज करने पर जोर यह है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे" को प्रकट करता है, यह अपनी खामोशी से, न्यायालयों के लिए अपना अपीलीय कार्य करना लगभग असंभव बना देता है। निर्णय की वैधता का निर्णय लेने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का कार्य या प्रयोग करना। तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक

प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कम से कम कारण न्यायालय के समक्ष मामले पर मन के अनुप्रयोग को इंगित करने के लिए पर्याप्त हैं।

एक अन्य तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष को पता चल सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का अस्पष्ट चेहरा" आम तौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत होता है।

उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। हम राज्य को अपील दायर करने की अनुमति देते हैं। उच्च न्यायालय अपील पर विचार करेगा और प्रत्यर्थियों को औपचारिक नोटिस के बाद अपील की सुनवाई करेगा और वर्तमान अपील में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित, कानून के अनुसार इसका निपटारा करेगा। अपील को इंगित सीमा तक अनुमति दी जाती है।

वी. एस. एस.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।